जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 133 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 19 मार्च, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

8 व 9 अप्रैल को कांग्रेस का अधिवेशन होगा अहमदाबाद में

ये अधिवेशन सरदार पटेल के 150वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। शायद कांग्रेस पुनः सरदार पटेल पर अपना कब्जा जताना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा ने सरदार पटेल को अपना ''आदमी'' घोषित सा कर दिया था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। एआईसीसी का अधिवेशन 8 एवं 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद नगर में आयोजित होगा, क्योंकि यह वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल का 150 वाँ जयन्ती वर्ष है, जिन्हें भाजपा अपने आदर्श के रुप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती रहती है।

जहाँ इस अधिवेशन के विस्तृत विवरण पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है, वहीं व्यवहारिक रुप में सत्र एक दिन का होगा तथा 9 अप्रैल को होगा। 8 अप्रैल की शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग होगी, जिसमें स्वीकृत हुये प्रस्ताव, अगले दिन अधिवेशन में पेश किये जायेंगे।

एक ऐसी पार्टी, जो विधानसभा चुनाव तथा तीन लोकसभा चुनाव हारती आ रही है, को एक ऐसा विस्तृत रोडमैप बनाना जरुरी है, जिस पर पार्टी आगे बढ़े तथा जहाँ पहुँचने की जरुरत है, वहाँ पहुँचे। लेकिन असली मुद्दों को उठाने तथा पिछले समय से होती आ रही गलतियों के मंथन एवं विश्लेषण के मामले में कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है।

- **अधिवेशन में पार्टी को कुछ गंभीर चिंतन करना होगा कि पार्टी कहाँ जा रही है, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं में यह भावना घर करती जा रही है कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है।**
- **राहुल गांधी के इर्द-गिर्द घूमने वाले नेता अब खुश हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी के युग के नेताओं से पार्टी को मुक्त करा दिया है और अब उनका एक ही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा राहुल की पसंद वाले लोगों को पार्टी में स्थान दिलवायें, जिससे राहुल के युवा समर्थक के हाथों में ही पार्टी का कामकाज रहे।**
- **राहुल इस बार यह नारा दे रहे हैं कि डीसीसी (डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी) को सशक्त किया जाए तथा डीसीसी को पार्टी के पावर स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाये और उनकी बात ऊपर तक सुनी जाए।**
- **अधिवेशन में चिंतन व निर्णय लेने की प्रक्रिया की ''खानापूर्ति'' जरूर होगी, पर, जमीन पर कुछ तब्दीलियां होने की गुंजाइश कम नज़र आ रही है।**

एक दिन के अधिवेशन में यह सब कुछ हो भी नहीं सकता, तथा पार्टी नेतृत्व का मानस अधिवेशन के आयोजन की ''खानापूर्ति'' करने का प्रतीत हो रहा है।

एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की है कि अगर नेतृत्व पार्टी की वस्तुस्थिति को सच्ची जाँच-परख नहीं करता तथा सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाता, तो 2029 के चुनावों की तैयारी के लिहाज से काफी देर हो चुकी होगी। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में ऐसी सोच बढ़ती जा रही है कि स्थितियाँ और समय उनके हाथों से फिसलते जा रहे हैं।

राहुल के इर्द-गिर्द रहने वाले मुट्ठी भर नेता, जिनका कांग्रेस की वर्तमान राजनीति पर नियंत्रण है, सोनिया गांधी के जमाने के नेताओं से नियंत्रण एवं अधिकार छीनने में सफल रहे हैं, और अब वे पार्टी में राहुल के जी-हुजूरों की संख्या बढ़ाने में लगे हुये हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पार्टी को अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंततोगत्वा धरती पर लौट रही हैं सुनीता

फ्लोरिडा, 18 मार्च। अंतरिक्ष में फंसे नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का यान धरती के लिए रवाना हो गया है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनके भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3.27 मिनट पर इसके फ्लोरिडा के तट पर उतरने की संभावना है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटने वाली हैं। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हो रही है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पृथ्वी पर लौटेंगे। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच की जाएगी और नासा इस यात्रा को लेकर अपडेट भी प्रदान करेगा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ महीनों तक रुकना पड़ा था।

- **9 माह तक अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के बाद अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व उनके साथी नासा के विशेष यान से धरती के लिए रवाना हो गए हैं।**

यूक्रेन व रूस के बीच ''सीज़फायर'' कराने की जल्दबाजी में ट्रम्प, पुतिन की हर बात मानते जा रहे हैं

यूक्रेन के कब्जे में बचे एकमात्र बंदरगाह ओडेसा को भी ट्रम्प, पुतिन को देने को राजी हुए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। यूक्रेन युद्ध में सीज़फायर लाने और ''डील'' पूरी करने की जल्दबाजी में अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा झुक गए हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हर बात मानते हुए दिख रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच ''एसैट्स'' के विभाजन पर मान गए हैं, इसमें रूस द्वारा हड़पी गई यूक्रेन की जमीन भी शामिल है।

ट्रम्प, पुतिन को कई फायदे पहुँचा सकते हैं, ओडेसा बंदरगाह भी रूस को सौंपा जा सकता है। रूस जाते समय अपने विमान में सवार पत्रकारों से ट्रम्प ने कहा कि एसैट्स शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा हुई।

यूक्रेन के पास सिर्फ एक विकल्प था, सीज़फायर एग्रीमैंट को स्वीकार करना। इन खबरों ने यूक्रेन से ज्यादा यूरोपियन यूनियन को हतप्रभ कर दिया है। पश्चिमी यूरोपीय देश अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि कई वर्षों तक उन्होंने अपनी सुरक्षा की अनदेखी की।

ट्रम्प ने रूस को जो राहतें देने की पेशकश की है, उसने इन देशों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब वे रूस की फायरिंग रेंज में आ गए हैं। इनमें यूक्रेन सबसे बुरी स्थिति में है। हर स्थिति में उसकी हार निश्चित है।

कुछ लीक हुई रिपोर्ट्स से संकेत मिला है कि यूक्रेन के पास जो एकमात्र बंदरगाह बचा है, उस ''ब्लैक सी का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **यह भी चर्चा है कि अमेरिका नाटो समझौते के तहत, यूरोप को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने वाला एग्रीमैंट भी रद्द करने का मन बना चुका है।**
- **इन चर्चाओं से यूरोपियन देश स्तब्ध हैं, क्योंकि वे अमेरिका के सुरक्षा कवच के इतने आदी हो गये हैं कि उनकी सेना में वह सामर्थ्य नहीं है कि वे यूरोप के देशों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले सकें।**
- **अपने हवाई जहाज पर सवार रूस जाते समय ट्रम्प ने साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि रूस से बहुत विस्तार से मंथन व बातचीत के बाद, इस सिद्धांत पर सहमति बन गई है कि रूस व यूक्रेन के बीच ''एसेट्स'' (सम्पत्ति व भूमि) का विभाजन होगा, जिन पर दोनों देशों ने दावा किया है कि वह उनकी सम्पत्ति है।**
- **इस विभाजन के सिद्धांत के तहत यूक्रेन का एकमात्र बंदरगाह व जमीन जिस पर रूस ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया है, रूस के हिस्से में आ गये हैं।**

दिन भर हंगामे के बीच लोकसभा नहीं चल पाई

विपक्ष इस माँग पर अड़ा रहा कि प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महाकुंभ के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए सदन में पेश प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। लोकसभा मंगलवार को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद दिन भर के लिये स्थगित कर दी गई। दरअसल, विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रयागराज में अभी-अभी सम्पन्न हुये महाकुंभ पर सदन में दिये गये बयान में भगदड़ का उल्लेख किये जाने की माँग की थी।

इससे पूर्व, जब प्रधानमंत्री महाकुम्भ के बारे में बोल रहे थे, उस समय लोकसभा हंगामे का माहौल था। विपक्षी सदस्य वैल में पहुँचे गये तथा वहाँ से बयान में भगदड़ की दुखान्तिका को शामिल किये जाने की माँग करते रहे। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुये, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ''महाकुम्भ हमारी परम्परा, इतिहास एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी शिकायत यह है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी, जिन्होंने महाकुम्भ में प्राण गँवाये। जबरदस्त हो -हल्ला के बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नियम 7 का उल्लेख किया और कहा कि यह नियम साफ कहता है कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, किन्हीं भी प्रश्नों पर ध्यान दिये बिना, बयान दे सकते हैं।

हंगामे के बीच, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को अपरान्ह 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया।

जब सदन की बैठक पुनः शुरु हुई तो विपक्षी सदस्य फिर वैल में इकट्ठे हो गये तथा जोर-जोर से नारे लगाने लगे। आसन द्वारा कहे जाने के बावजूद, वे लोग अपनी सीटों पर नहीं आये, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 'डिमान्ड्स फॉर ग्रान्ट्स फॉर रेलवे मिनिस्ट्री' पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे।

इसके बाद, ''ग्रान्ट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पर बहस शुरु होने से पहले ही, अध्यक्ष ने लोकसभा दिन भर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **राहुल गांधी ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, उनको श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, प्र.मंत्रीके प्रस्ताव में**
- **लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला ने व्यवस्था दी कि 37 नम्बर रूल के अनुसार, प्र.मंत्री या कोई भी अन्य मंत्री सदन में वक्तव्य दे सकता है, बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिये।**

'आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की कार्यवाही जल्द शुरू होगी'

जयपुर, 18 मार्च। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एक बैठक में फैसला लिया कि उसके द्वारा जारी किये गये मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जायेगा। दरअसल मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने गृहमंत्रालय के सचिव, विधायिकी विभाग के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अफसरों व तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अफसरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में लिया गया यह अहम् फैसला।**

नागपुर के दंगे के लिए कौन जिम्मेवार?

तीन थ्योरियाँ चर्चित हैं, इस सवाल के जवाब में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। क्या नागपुर हिंसा विकी कौशल-अमिनीत फिल्म ''छावा'' द्वारा उकसायी गई थी? क्या यह महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के सम्बंध में की गई टिप्पणी की प्रतिक्रिया थी? या फिर, क्या यह हिंसा एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की उकसाने वाली टिप्पणियों के कारण भड़की थी?

दंगे की जिम्मेदारी के प्रश्न को लेकर बढ़ते हुये राजनैतिक दोषारोपण के बीच, उपरोक्त तीन प्रश्न इस समय आम चर्चा में हैं।

शिवसेना (शिंदे) सांसद नरेश म्हास्के ने ओवैसी पर दोषारोपण करते हुये कहा है कि ''सारा देश जानता है कि ओवैसी जैसे लोग, स्वयं को नेता सिद्ध करने के लिये, इस प्रकार के कृत्य करते हैं। वे इस प्रकार के दंगे कराके अपनी नेतागीरी को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। (इस पूरे मामले की) जाँच होनी चाहिये।'' दूसरी तरफ, ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर उसके खुफिया तंत्र की असफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मंत्रियों द्वारा दिये गये उकसाऊ भाषणों ने माहौल को उत्तेजित और आवेशित किया था।

इस बीच, कॉंकावली के भाजपा विधायक नितेश राणे ने सपा नेता अबू आजमी पर दोषारोपण किया है। उन्होंने कहा, ''आजमी (हिंसा के) जिम्मेदार हैं। यह मुद्दा उन्होंने ही शुरु किया था। यह सरकार को बदनाम करने के लिये पूर्व- नियोजित हिंसा थी। हम उन लोगों को नहीं बख्शेंगे, जिन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाये हैं। (उनके खिलाफ) सख्त कार्यवाही की जायेगी।''

प्रसंगवश बता दें कि आजमी ने हाल ही में कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में, भारत की जीडीपी, विश्व की जीडीपी की 24 प्रतिशत थी तथा इसकी आर्थिक समृद्धि के कारण, भारत को उस समय ''सोने की चिड़िया'' कहा जाता था।'' लेकिन, इसके बाद सपा नेता ने अपना बयान वापस ले लिया था।

मंगलवार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि ''छावा'' फिल्म, जिसमें विकी कौशल और रश्मिका मन्दाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, ने औरंगजेब के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा किया था। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र शम्भाजी महाराज के जीवन की ऐतिहासिक प्रस्तुति है। विदित ही है कि औरंगजेब के शासन काल में, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से युद्ध किया था।

इसी बीच यह एक और कारण उभरकर आया है कि हिंसा इन अफवाहों के कारण हुई कि विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल के एक्टिविस्टों ने मुस्लिमों का पवित्र ग्रन्थ जला दिया है। ये ऐक्टिविस्ट विरोध-प्रदर्शन करते हुये, औरंगजेब के मकबरे को तोड़े जाने की माँग कर रहे थे।

- **क्या विक्की कौशल की फिल्म छावा से सांप्रदायिक भावनाएं उत्तेजित होने से दंगा हुआ?**
- **क्या सपा नेता अबु आज़मी के महाराष्ट्र की विधानसभा में औरंगज़ेब के बारे में की गई टिप्पणी से दंगा भड़का?**
- **या एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उत्तेजक भाषण से सांप्रदायिक भावनाओं को हवा मिली और दंगा विकराल हुआ।**

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपरलीक मामले में एक और सब इंस्पैक्टर गिरफ्तार

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 18 मार्च। पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपरलीक मामले में एसओजी ने एक ओर आरोपी मोनिका को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीशनल डी.जी.पी. वी.के. सिंह ने बताया कि चयनित उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) मोनिका (उम्र 25 वर्ष) सुल्तानपुर (जिला झुंझुनूं) की निवासी है, और उसे सीकर जिले के दादिया पुलिस थाने के अफसरों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मोनिका ने उप निरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर दिनांक 15 सितंबर 2021 को अजमेर के परीक्षा केन्द्र पर दिये थे।

एसओजी द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया मोनिका ने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से मिलकर परीक्षा पास करने के षडयंत्र में भाग लिया था। एसओजी के अनुसार पौरव कालेर ने मोनिका को उप निरीक्षक पुलिस की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **एसओजी के एडीशनल डीजीपी वीके सिंह ने बताया कि आरोपी मोनिका ने पेपरलीक सरगना पौरव कालेर से ''चीटिंग'' करने के लिये 15 लाख रुपये में सौदा किया था।**

न्यूज़ीलैंड के प्र.मंत्री ने राहुल गांधी से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 18 मार्च। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत यात्रा पर आये न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्स से आज मुलाकात की।

कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच आज सुबह यहां मुलाकात हुई जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

- **कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने आर्थिक व सांस्कृतिक मसलों पर चर्चा की।**

पार्टी ने कहा गांधी और लक्सन की यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। मुलाकात को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने इस दौरान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। यह मुलाकात भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

'भारत ने अमेरिका से आयातित सामान पर टैरिफ हटाने का कोई समझौता नहीं किया है'

भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने संसदीय समिति के समक्ष स्पष्ट कहा कि भारत ने ट्रम्प का दबाव स्वीकार नहीं किया है तथा अमेरिका से आयातित सामान पर ''टैरिफ'' हटाने पर कोई सहमति नहीं दी है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। भारत ने अमेरिका के दबाव में अपनी टैरिफ नीति में बदलाव नहीं किया, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमें इसके विपरीत यकीन दिलवा रहे थे। असल में भारत ने टैरिफ कटौती पर अमेरिका के दबाव को मानने से दृढ़ता से मना कर दिया। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के दावे को झुठलाते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने संसदीय पैनल को जानकारी दी कि भारत ने अमेरिकन सामान पर टैरिफ में कटौती करने की बात नहीं मानी है। बर्थवाल का बयान ट्रम्प के इस दावे का खंडन करता है कि नई दिल्ली ने टैरिफ कटौती की बात मान ली है।

ट्रम्प का दावा कि, भारत टैरिफ कटौती के लिए मान गया है, बढ़ा-चढ़ाकर बोला गया है और बेहद अपरिपक्व है। हालांकि, कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे मोटर साइकिल, बॉरबन व्हिस्की पर टैरिफ कटौती हुई है, पर भारतीय अधिकारियों ने कहा, टैरिफ कटौती का कोई बड़ा एग्रीमैंट नहीं हुआ है।

बर्थवाल ने कहा कि भारत की ट्रेड पॉलिसी उदारीकरण और रणनीतिक संरक्षणवाद के बीच के संतुलन पर आधारित हैं। हालांकि, भारत द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड को भी प्रोत्साहित करता है। बर्थवाल ने चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से, खासकर कुछ घरेलू क्षेत्रों में टैरिफ कटौती करने से गंभीर आर्थिक दबाव पैदा हो सकता है जिससे मंदी आ सकती है। नई दिल्ली टैरिफ कटौती पर गंभीरता से विचार करेगा तथा उसी जगह टैरिफ कटौती की जाएगी, जहाँ देश के हितों को नुकसान न पहुँचे।

इसी बीच चीन इकोनॉमिक डायवर्सिफिकेशन और कूटनीतिक तरीकों व घरेलू सुधारों से अमेरिका के टैरिफ का लगातार जवाब दे रहा है। चीन ने दोहरे प्रसार की नीति अपनाई है। यह घरेलू उपभोग मजबूत कर रहा है और निर्यात में भी अपना दबदबा कायम रखे हुए है। वह साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ चीन व्यापारिक सहयोग बढ़ा रहा है तथा अमेरिकी बाज़ार पर निर्भरता कम कर रहा है। चीन की रीजनल कॉम्प्रैहैन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आर.सी.ई.पी.) वैकल्पिक क्षेत्र खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

चीन बैल्ट एण्ड रोड इनिशिऐटिव योजना का भी सहारा ले रहा है। नए देशों के साथ आर्थिक समझौते करने के लिए और सुनिश्चित कर यहाँ उसके सामान का निर्यात हो। चीन वित्तीय रूप से अपनी मुद्रा युआन के अंतर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता कम हो सकें।

यूएस टैरिफ के जवाब में चीन ने राजनैतिक रूप से संवेदनशील अमेरिकी सामान जैसे एल.एन.जी. और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **ट्रम्प का यह दावा कि भारत ने टैरिफ में भारी कमी करने का निर्णय लिया है। यह पूर्णतया सत्य नहीं है। यह एक अतिशयोक्ति है, कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर, जैसे मोटर साइकिल व बॉरबन व्हिस्की पर टैरिफ कम किया है।**
- **भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार, भारत की टैरिफ कम करने की नीति, उदारवाद व स्थानीय इण्डस्ट्री की सुरक्षा के बीच संतुलन बैठाने के सिद्धांत पर आधारित है।**
- **अधिकारियों के अनुसार, ''टैरिफ रिडक्शन'' पर बातचीत जरूर होगी, पर, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा।**